P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

परिवर्तित वैश्विक राजनीति : विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन में सुधारों की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

सारांश

विगत दो दशकों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मौद्रिक एवं व्यापार व्यवस्थाओं के प्रबंधन हेतु प्रतिबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं विशेषकर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि के संबंध में सुधार एवं पुनःसंरचना हेतु विकासशील राष्ट्रों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है तथा यह विषय अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में उत्तर–दक्षिण वार्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक/कारक बनता जा रहा है।[1]

मुख्य शब्द : अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विकासशील राष्ट्र।

राजेश कुमार टांक
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विषयो के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य विषयों के प्रबन्धन हेतु ब्रेटनवुड्स व्यवस्था की स्थापना की गई। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन की ब्रेटनवुड्स व्यवस्था ने बड़े–बड़े औद्योगिक राज्यों के बीच वाणिज्यिक एवं वित्तीय संबंधों के लिए नियमों की रचना की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नियमन के लिए नियमों, संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की व्यवस्था का निर्धारण करने के साथ – साथ ब्रेटनवुड्स के योजनाकारों ने पुनःनिर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। ब्रेटनवुड्स समझौते का उद्देश्य था ऐसे नियमों व संस्थात्मक संरचना की स्थापना करना ताकि स्वर्णमानक की समस्या तथा अन्तःयुद्धकाल की अस्तव्यस्तता से मुक्ति को सुनिश्चित किया जा सके।[2]

वास्तव में इन संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वाणिज्यिक विषयों का बेहतर प्रबंधन कर एकसमान वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना था जो वैश्विक शांति, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि की निरन्तरता को सुरक्षित बनाए रख सके। कुछ वर्षों पश्चात् ही इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं संरचना को लेकर विसंगतियाँ उत्पन्न होने लगी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को विकृत कर दिया। तत्पश्चात् तीसरे विश्व के आन्दोलन गुट निरपेक्ष द्वारा औपचारिक रूप से न्याय आधारित – समतामूलक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवाज मुखर की गई। जिस हेतु वर्ष 1964 में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना की गई ताकि इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को गति दी जा सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विकासशील देशों के अनुरूप लाभदायक बनाया जा सके।[3]

साहित्यावलोकन

1. तपन बिस्वाल अपनी पुस्तक ''अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में लिखते हैं कि शीतयुद्ध काल में निर्मित ब्रेटनवुड्स संस्थाएँ पिछले 60 वर्षो से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इन संस्थाओं का वास्तविक लक्ष्य वैश्विक आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बनाए रखना है।
2. बेरनार्ड हॉकमैन अपने ''पॉलिसी रिसर्च वकिंग पेपर : प्रोपोजल्स फॉर डब्ल्यू टी ओ रिफॉर्म'' में लिखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वाणिज्य व्यवस्था का संचालन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यावश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न विसंगतियों एवं वित्तीय संरचनाओं की विफलता ने समय–समय पर ब्रेटनवुड्स व्यवस्था में पुनःसंरचना की माँग को मुखरता दी हैं। परिणामस्वरूप विश्व की उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने एकजुटता से इस हेतु समन्वित प्रयास प्रारम्भ किए। जिनमें इब्सा, ब्रिक्स, शंधाई सहयोग संगठन इत्यादि प्रमुख हैं। दूसरी ओर लैटिन अमेरीकी राष्ट्रों ने

इन संस्थाओं को पूँजीवादी मानसिकता की उपज मानकर स्वयं के लिए पृथक मुद्रा एवं बैंक की स्थापना तक कर ली हैं।[4]

विकसित एवं औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक बाधाओं द्वारा विकासशील राष्ट्रों के व्यापार को अवरूद्ध करना, इस सन्दर्भ में विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षित भूमिका में गिरावट, कोटा तय करने के प्राचीन मानक, मत व्यवहार को लेकर विसंगति, उच्च पदों पर पदस्थ व्यक्तियों की स्थिति इत्यादि ने इन संस्थाओं में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सुधारों की माँग को व्यवहार्य बना दिया हैं। ताकि एक स्थिर, शांत एवं समृद्ध वैश्विक समाज की रचना की जा सके। वर्ष 2011 में विश्व बैंक तथा गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक प्रबंधन नेटवर्क के तत्वावधान में बेरनार्ड हॉकमैन द्वारा विश्व व्यापार संगठन में सुधार हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।[5]

वर्तमान वैश्विक वित्तीय प्रणाली में परिवर्तन

ब्रेटनवुड्स संस्थाओं की उत्पत्ति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में निरन्तर अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में अनेक राष्ट्र आर्थिक एवं तकनोकी दृष्टि से शक्ति सपन्न उभरे है तो दूसरी ओर विश्व के विकसित एवं औधोगिक रूप से सम्पन्न राष्ट्रों की शक्ति में ह्रास हुआ है। वर्ष 2008 में अमेरिका में आये सब–प्राइम वित्तीय संकट तथा वर्ष 2010–11 में यूरोजोन में आये वित्तीय संकट ने एक तरफ जहाँ अमेरिकी तथा यूरोपीयन अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक दृष्टि से अस्त–व्यस्त एवं कमजोर हो रही थी तब उसी समय भारत एवं चीन जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो उभर रही थी।[6]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचनाओं में सुधार की आवश्यकता

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की संरचना 20वीं शताब्दी के मध्य की स्थिति के समकक्ष स्थिर है जो वर्तमान में परिवर्तित शक्ति वास्तविकताओं एवं चुनौतियों के अनुरूप नहीं है। इन संस्थाओं में पुनःसुधार एवं इनकी पुनःसंरचना का एकमात्र उद्देश्य वैश्विक शांति, समृद्धि, स्थिरता एवं विकास की निरन्तरता को सुरक्षित बनाए रखना है। अतः इनके पनःसुधार एवं पुनःसंरचना की आवश्यकता निरन्तर महसूस की जा रही है।[7]

उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक से ही ब्रेटनवुड्स संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं संरचना को लेकर विकासशील विश्व ने इनके विरोध में आवाज उठाना प्रारम्भ कर दिया था। जब सम्मिलित रूप में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की माँग की गई। परिणामस्वरूप वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण – दक्षिण सहयोग (विकासशील देशों का आपसी सहयोग) को बढ़ावा देना था ताकि विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता कम हो सके।[8]

अंकटाड का मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान कर पाने में पूर्ण रूप से संगठित नहीं हैं। 21 अप्रैल, 2012 को UNCTAD की कतर (दोहा) में 13वीं बैठक में विकासशील देशों की उन्नत भागीदारी एवं वैश्विक वित्तीय संस्थाओ में सुशासन एवं जवाबदेही पर बल दिया गया।[9]

अध्ययन का उद्देश्य

अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार कर उनको समकालीन वैश्विक व्यवस्था के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना

निश्कर्श

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत उन प्रस्तावों का समूह था जिसमें विकासशील देशों ने व्यापार की शर्तों में सुधार, विकास सहायता में वृद्धि, विकसित देशों के प्रशुल्क दरों में कमी, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का पुनःनिर्धारण कर इनके प्रबन्धन में विकासशील देशों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना और अन्य माध्यमों द्वारा अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।[10]

अंत टिप्पणी

1. *बिस्वाल तपन, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, ओरिएंट ब्लेकस्वान पब्लिशर्स, पृ.सं 38 – 2013*
2. *बिस्वाल तपन, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, ओरिएंट ब्लेकस्वान पब्लिशर्स, पृ.सं 41*
3. *खन्ना बी.एन., अरोड़ा लिपाक्षी, भारती की विदेश नीति विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा. लिमिटेड पृ.सं 102 – 2009 ।*
4. *सुन्दरम जोमो क्वामे, रिफॉर्मिंग द इन्टरनेशनल फाइनेंशीयल सिस्टम फॉर डेवलपमेन्ट, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयॉर्क पृ.सं 178 – 2010*
5. *हॉकमैन बेरनार्ड, पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सीरीज 5525 वर्ल्ड बैंक प्रोपोजल्स फॉर डब्लू टी ओ रिफॉर्म्स :ए सिंथेसिस एंड असेसमेंट*
6. *कोर मार्टिन, प्रोपोजल्स टू रिफॉर्म्स द इन्टरनेशनल फाइनेशियल सिस्टम, वर्किंग पेपर– 2011*
7. *कॉफी एण्ड रिले रॉबर्ट, रिफोर्म ऑफ द इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूशन, एडवर्ड एल्गार पब्लिशर्स, पृ.सं 82 – 2006*
8. *टारूल्लो डेनियल. के., Georgtown University Law Center एरिफोर्मिंग की इन्टरनेशनल फाइनेंशीयल इन्स्टीट्यूशन फॉर द 21st सेन्चुअरी, पृ.सं 24 – 2007*
9. *अन्नान कोफ़ी, संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ''रिफॉर्म ऑफ द इन्टरनेशनल मॉनेटरी एण्ड फाइनेंशियल सिस्टम'' 2011*
10. *फिशर स्टेनली, फाइनेंशियल क्राइसिस एण्ड रिफोर्म ऑफ द इन्टरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, आइएमएफ (IMF)– 1998*